जनसत्ता

गड़बड़ी की उड़ान

एअर इंडिया के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से बड़े पैमाने पर यात्रियों को हुई असुविधा ने एक बार फिर उड्डयन संबंधी प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एअर इंडिया के सर्वर में शनिवार तड़के खराबी आ गई, जिसकी वजह से देश और दुनिया भर में उसकी सेवाएं प्रभावित हुईं। इस गड़बड़ी को ठीक करने में करीब छह घंटे लग गए। इस दौरान हजारों यात्री अलग-अलग हवाईअड्डों पर फंसे रहे। फिर जब सेवाएं शुरू हुईं, तो अगले दिन भी वे देर से संचालित होती रहीं। हालांकि एअर इंडिया और इसके संचालन संबंधी सर्वर की व्यवस्था संभाल रही कंपनी सीटा के प्रबंधन ने यात्रा में आए व्यवधान के लिए मुसाफिरों से क्षमा याचना की, पर अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि यह गड़बड़ी किन वजहों से आई और उसे दूर करने में इतना समय क्यों लगा। एअर इंडिया की सेवाओं के मामले में पहले ही मुसाफिरों का भरोसा कमजोर है। उसमें लेट-लतीफी आम बात है। निजी विमान कंपनियों की तुलना में उसकी सेवाएं कड़ी चुनौती के दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उसकी सेवाओं में इतने लंबे समय तक रुकावट स्वाभाविक रूप से मुसाफिरों के मन में नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी।

विमान सेवाओं का सहारा लोग इसलिए लेते हैं कि वे लंबी दूरी की यात्रा कम समय में पूरी कर सकें। बहुत सारे लोग दफ्तरी कामकाज, किसी आवश्यक कार्य, व्यावसायिक जरूरतों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आदि के चलते विमान सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस तरह समय पर न पहुंच पाने की वजह से कई लोगों को भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। फिर अनावश्यक रूप से हवाईअड्डों पर पांच-छह घंटे अपने विमान का इंतजार करना कम त्रासद नहीं होता। मगर एअर इंडिया तमाम विवादों, विरोधों, यात्रियों की नाराजगी के बावजूद अपनी सेवाओं में सुधार नहीं कर पा रहा। अक्सर उसके विमान समय पर नहीं पहुंचते या उड़ान भरते। खासकर सर्दी के मौसम में कोहरा, धुंध आदि के बहाने उनमें देरी एक स्थायी समस्या की तरह बनी हुई है। कई बार अंतिम समय में सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं। हवाईअड्डे पहुंचने के बाद मुसाफिरों को इसकी जानकारी मिलती है और वे नाहक परेशान होते हैं। उनमें बहुत सारे मुसाफिर ऐसे होते हैं, जिन्होंने कई दिन पहले से टिकट खरीद रखी होती है और हवाईअड्डे पहुंचने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि विमान देरी से उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, तो उनके पास दूसरे विमान की सेवाएं लेने का विकल्प भी नहीं होता।

अभी जेट एअरवेज की सेवाएं बंद होने से उड्डयन क्षेत्र में काफी अफरा-तफरी का माहौल है। दूसरी विमानन कंपनियों पर मुसाफिरों का बोझ बढ़ा है। ऐसे में सरकारी कंपनी होने के नाते एअर इंडिया की जिम्मेदारी अधिक है। मगर उसकी कार्यशैली में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। जेट के बंद होने और उसकी सेवाओं के हस्तांतरण, उड़ान समय की खरीद आदि को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी लग रहे हैं। इस तरह कई लोग स्वाभाविक रूप से एअर इंडिया के सर्वर में हुई गड़बड़ी को भी शक की नजर से देख रहे हैं। हालांकि तकनीकी गड़बड़ी कभी भी, कहीं भी हो सकती है, पर विमान सेवाओं के मामले में ऐसी गड़बड़ी को सामान्य खराबी मान कर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इससे न सिर्फ एअर इंडिया के कारोबार पर, बल्कि पूरे उड्डयन क्षेत्र की साख पर असर पड़ेगा।

हादसा और सवाल

शायद ही कोई साल ऐसा गुजरता हो जब हमारी नौसेना के किसी जहाज से हादसे की कोई खबर न आती हो। ताजा हादसा शुक्रवार को नौसेना के विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य पर हुआ। इस हादसे में एक अधिकारी की जान चली गई। कर्नाटक के करवार बंदरगाह के पास यह हादसा तब हुआ जब पोत बंदरगाह में दाखिल हो रहा था। तभी पता चला कि इंजन वाले हिस्से में आग लग गई है और आग फैलती हुई ऊपर तक आ गई। जहाज पर मौजूद कर्मियों की सजगता से आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन धुएं से एक लेफ्टिनेंट कमांडर बेहोश हो गए। उन्हें नौसेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। नौसेना के इस जांबाज अधिकारी ने अपनी जान देकर जहाज को एक बड़ा हादसे से बचा लिया, वरना आग जिस तेजी से फैल रही थी, उससे यह हादसा जल्द गंभीर रूप धारण कर सकता था।

ऐसे हादसे सेना और सरकार दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय होने चाहिए। आइएनएस विक्रमादित्य का हादसा सैन्य जहाजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। आइएनएस विक्रमादित्य कोई छोटा-मोटा जहाज नहीं है, बल्कि इसे नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक बेड़ा माना जाता है। इस हादसे के बाद सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि तीन साल पहले भी इस पर एक बड़ा हादसा हो गया था। तब इस जहाज पर जहरीली गैस रिसने से दो सैन्यकर्मियों की मौत हो गई थी। इसलिए यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर क्या कारण हैं कि हमारे जहाज ऐसे हादसों के शिकार हो रहे हैं जो जानलेवा साबित होते हैं। कहने को आसानी से यह तर्क दिया जा सकता है कि इतने बड़े जहाजों पर ऐसे हादसे सामान्य बात हैं और इनसे निपटने के पूरे इंतजाम रहते हैं। आइएनएस विक्रमादित्य पर आग से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने की बात भी कही गई है और बताया गया है कि इस हादसे से इसकी लड़ाकू क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे छोटे-छोटे हादसे ही बड़े विनाश का कारण भी साबित होते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। आग हो या चिनगारी, जहाज पर ऐसा हादसा हुआ ही क्यों, यह गंभीर जांच का विषय है।

बात दरअसल उस पुख्ता सुरक्षा की है, जिसके अभाव में ऐसे हादसे होते हैं। आज जिस तरह की अत्याधुनिक तकनीक, कंप्यूटरीकृत प्रणालियों और संचार सुविधाओं से परिपूर्ण जहाज हैं, उसमें जोखिम की आशंका अतिन्यून ही नहीं बल्कि शून्य होनी चाहिए। लेकिन होता यह आ रहा है कि हर हादसा हमें चेता रहा है और हम किसी भी हादसे से कोई सबक नहीं ले रहे। जाहिर है, खामी कहीं न कहीं हमारे तंत्र में ही है। लेकिन हम उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत यह है कि आइएनएस विक्रमादित्य मूल रूप से रूसी पोत एडमिरल गोर्शकोव का ही परिवर्द्धित रूप है जिसे रूस ने भारतीय नौसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया था। नौसेना के पास अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे जहाज और उपकरण हैं जो पुराने पड़ चुके हैं और इन्हीं के सहारे हमारे जवान पानी में पहरा दे रहे हैं। सवा दो अरब डॉलर की लागत वाले आइएनएस विक्रमादित्य को पांच साल पहले ही रूस से पट्टे पर लिया गया था। इस पर तीस लड़ाकू विमान और हेलिकॉप्टर और डेढ़ हजार से ज्यादा जवान तैनात किए जा सकते हैं। इसलिए इस पर अगर कोई हादसा होता है तो चिंता होना और सवाल उठना लाजिमी है।

कल्पमेधा

जो व्यक्ति निश्चय कर लेता है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है।

– इमर्सन

सभ्यताओं की लड़ाई

ब्रह्मदीप अलूने

> इस दौर में वैश्विक समुदाय सुरक्षा को लेकर अस्थिर और भयभीत है। शांति सुनिश्चित करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र भी लाचार नजर आता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया को युद्ध के खतरे से लगातार बचाने में कामयाब संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद का सामना करने में लाचार साबित हुआ है। उसकी यह बेबसी दुनिया को सभ्यताओं की नई और खतरनाक लड़ाई की ओर धकेल रही है।

अमेरिकी राजनीतिक शास्त्री हटिंग्टन का विचार था कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में संघर्ष का कारण राष्ट्रों के बीच विचारधाराओं के मतभेद के बजाय बड़ी सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक अंतर होगा। हटिंग्टन ने एक विचार प्रतिपादित किया था जिसे 'सभ्यताओं का संघर्ष' नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद आठवें दशक में वैश्विक आतंकवाद की समस्या जिस प्रकार जोर पकड़ती गई और आज दुनिया के ज्यादातर देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, उससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्र या विचारधारा से अलग लोगों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान ही संघर्षों का मुख्य कारण बनती जा रही है।

दरअसल, दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत शांत देश श्रीलंका में ईसाइयों को निशाना बना कर किए गए खौफनाक आतंकी हमलों से इस बात को बल मिला है कि आधुनिक समय में सबसे बड़ी चुनौती वह कट्टरता है जो सभ्यताओं को एक दूसरे के सामने खूनी संघर्ष के लिए खड़ा कर रही है। कथित इस्लामिक चरमपंथियों ने ईसाइयों के त्योहार ईस्टर के आयोजन को ठीक उसी तरह निशाना बनाया, जैसे न्यूजीलैंड में पिछले महीने मुसलिम धर्मावलंबियों को बनाया गया था। मसुलिम समुदाय के लोगों को जुमे के दिन मस्जिद में निशाना बनाया गया था, वहीं श्रीलंका में ईस्टर संडे के दौरान बड़ी संख्या में लोग चर्चों में जुटे थे। इसी दौरान राजधानी कोलंबो के तीन चर्चों को निशाना बनाया गया।

न्यूजीलैंड और श्रीलंका की भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में जमीन-आसमान का अंतर है। लेकिन इन सबके बावजूद आतंकी हमले की जड़ें सभ्यताओं के संघर्ष में नजर आ रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और दुनिया के नक्शे पर बहु-सांस्कृतिक परिवेश वाले राष्ट्र उभरे। इसके साथ ही वैश्विक सहयोग के कारण धार्मिक कट्टरता के कम होने की परिस्थितयां भी बनीं। लेकिन समय के साथ महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से मानवीय विकास को बाधित कर दिया। इसके बाद के कुछ दशकों में दुनिया के कई भागों में धर्मनिरपेक्षता की लहर चली। वामपंथ, दक्षिणपंथ और उग्र राष्ट्रीयता का विकास हुआ। महाशक्तियों ने अस्सी के दशक में पिछड़े राष्ट्रों का आक्रामक उपयोग करने के लिए इसे जिहाद की ओर मोड़ दिया। अब इसने दुनियाभर में अति दक्षिणपंथी आतंकवाद का घिनौना आकार ले लिया है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न राष्ट्रों में लोकतांत्रिक सत्ताएं लगातार राजनीतिक संकीर्णता को बढ़ावा दे रही हैं। इससे धार्मिक अल्पसंख्यक प्रभावित हो रहे है और डिजिटल युग में धार्मिक, जातीय और आतंकी संगठन इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने में आसानी से सफल हो रहे हैं। आइएसआइएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन इन परिस्थितियों का फायदा उठा कर दुनिया को मध्ययुगीन संघर्ष की ओर धकेलने में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। श्रीलंका में आतंकी हमले के बाद इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने अपने मीडिया पोर्टल के जरिए इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इसमें दावा किया गया है कि जिन हमलावरों ने श्रीलंका के ईसाइयों को निशाना बनाया था, वे इस्लामिक स्टेट के लड़ाके थे।

बीसवी शताब्दी के फ्रांसिसी सैन्य विचारक कैप्टन लिडिल हार्ट ने एक बार कहा था-'यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझिए।' इस दौर में वैश्विक समुदाय सुरक्षा को लेकर अस्थिर और भयभीत है। शांति सुनिश्चित करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र भी लाचार नजर आता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया को युद्ध के खतरे से लगातार बचाने में कामयाब संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद का सामना करने में लाचार साबित हुआ है। उसकी यह बेबसी दुनिया को सभ्यताओं की नई और खतरनाक लड़ाई की ओर धकेल रही है।

न्यूजीलैंड की घटना में मुसलिमों के प्रति जो घृणा हत्यारे ने दिखाई थी और मस्जिदों पर हमले में लोगों के मारे जाने के बाद दुनिया के कई देशों के दक्षिणपंथी इसे जायज ठहराने की कोशिश कर रहे थे, वह बिल्कुल वैसा ही था जब अमेरिका पर हमले को लेकर कई मुसलिम देशों में खुशियां मनाई गई थी और पटाखे फोड़े गए थे। इन घटनाओं में यह साफ प्रतीत हो रहा है कि दुनिया में सभ्यताओं की आपसी प्रतिद्वंद्विता नफरत और पागलपन के रूप में बढ़ती जा रही है और समाज का पढ़ा-लिखा तबका भी धर्मांधता के जाल में बुरी तरह उलझ कर आतंकी व्यवहार की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक समाज में सार्वभौमिकता के सारे तर्कों पर धर्मांधता हावी होती दिखाई पड़ रही है और इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं।

सभ्यताओं के इस संघर्ष को बढ़ावा देने में इंटरनेट का प्रमुख योगदान सामने आ रहा है। डिजिटल दुनिया के आतंकी गठजोड़ से निकले कट्टर मजहबी आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वास्तव में इस दौर में सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल दुनिया से उभरा आतंकवाद ही है जो इंटरनेट के जरिए बेलगाम होकर जानलेवा भी हो जाता है। धर्म के आधार पर दिग्भ्रमित कर आइएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन ने युवाओं को खतरनाक लक्ष्यों की और मोड़ देने में महारत हासिल कर ली है। दुनिया भर के देशों में नौनिहालों को कट्टरता के प्रभाव से बचाने के लिए शिक्षा संस्थानों में 'काउंटर रेडिकलाइजेशन' जैसे कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है। कई देशों ने विश्वनीय धमर्गुरुओं और कानूनी जानकारों का इस्तेमाल किया है जो हिंसक जेहाद और भ्रम में पड़े जेहादियों से अलग रहने का प्रचार करते हैं। वास्तव में सोशल मीडिया पर कट्टरपंथ का प्रचार रोकना दुनिया के सामने बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग आतंकवाद बढ़ा रहा है और इसे लेकर किसी विश्वव्यापी योजना पर काम करने की जरूरत है।

श्रीलंका में हुए आतंकी हमले में आइएस का मददगार जो गुट बताया जा रहा है वह श्रीलंका का ही एक एक स्थानीय जेहादी गुट- नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) है। यहां यह भी महत्त्वपूर्ण है कि आत्मघाती हमलावर भी स्थानीय बताए जा रहे हैं। और संदिग्ध हमलावरों के बारे में श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री रुवान विजयवर्दने ने बताया है कि अधिकांश हमलावर शिक्षित हैं और आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से आते हैं। जाहिर है, अलकायदा की पत्रिका 'इंस्पायर' में आतंकी हमलों के नुस्खों को आजमा कर दुनियाभर के कई उच्च शिक्षित युवा आतंक की राह पर चल पड़े हैं और इन्हें किसी भी राष्ट्र की सीमाओं में बांध कर नहीं रखा जा सकता।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को बेहद महत्त्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न देश अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे समान सोच वाले राष्ट्रों के साथ मिल कर काम करते हैं, संकट की घड़ी में, युद्ध के समय एक दूसरे के साथ होते हैं। संयुक्त राष्ट्र, नाटो, सिएटो या वारसा पैक्ट या आर्थिक आधार पर जो देश साथ आए हैं, उनके आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक हित रहे हैं। लेकिन इसमें से कोई भी संगठन वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिकता या सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने में सफल नहीं हो सका है और आज यह सबसे बड़ी जरूरत बन गया है।

श्रीलंका में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। देश की कुल आबादी का सिर्फ 9.7 फीसद ही मुसलमान हैं। इसमें से अधिकांश श्रीलंका की संस्कृति में रचे-बसे हैं। श्रीलंका में हुए हाल के आतंकी हमलों के बाद इनका जीवन कठिन होगा और ये सरकार की निगरानी और अन्य धर्मावलंबियों के निशाने पर होंगे। दरअसल संकट यही है कि लोगों को यह समझना होगा कि दुनिया का भविष्य इससे तय होगा की हममें क्या समानताएं हैं, उन बातों से नहीं जो हमें अलग करती है या संघर्ष की ओर ले जाती हैं।

परिवेश का पाठ

कालू राम शर्मा

दुनिया मेरे आगे

पौने दो बरस की जुगनू के साथ जब भी समय बिताता हूं तो उसमें अपार कौतूहल पाता हूं। हालांकि सीमित अनुभवों के चलते उसे यह खयाल नहीं रहता कि गली या सड़क पर कोई वाहन आ रहा है। खाना खाते वक्त यह चिंता किए बिना कि गर्म है, उसे छूने की कोशिश करती है। इन सबके प्रति हम वयस्कों को खासा खयाल रखना होता है। दरअसल, हम वयस्क भी अनुभवों से ही बहुत कुछ सीखते हैं जो हमें अपने परिवेश से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं। जुगनू अपने परिवेश की उन तमाम चीजों और व्यवहारों को समझती है, जिनसे उनका वास्ता पड़ता रहता है। वह अपने संदर्भ की चीजों के साथ खेलती है।

मैं बच्चों की रंग-बिरंगी पत्रिका 'प्लूटो' को खोल कर पन्नों को उलट रहा था। तभी जुगनू ने मुझसे पत्रिका हथिया ली। रंग-बिरंगी पत्रिका अब उसके हाथों में थी और मैं उसकी हरकतों को देख रहा था। मुझे एक अनूठा अनुभव हुआ, जिसने मुझे बच्चों की असीमित क्षमता का एहसास कराया। यों पौने दो बरस की बच्ची अब तक अपने परिवेश में तमाम जानवरों, कीट-पतंगों, बस, ट्रक, कार, रेल, साइकिल और तमाम व्यवहारों, मसलन गुस्सा, प्यार, लेन-देन, चीजों को उठाना, जमाना वगैरह जैसी क्रियाओं से परिचित हो चुकी थी, जिनसे उसका जाने-अनजाने में वास्ता पड़ता है। मैंने यों ही पत्रिका के लाल रंग के कवर की ओर उसका ध्यान खींचा। बाईं ओर एक चित्र बना देख कर वह तुतलाते हुए बोली- 'तींती' (चींटी)। मुझे याद आया कि जब वह बरामदे की मुंडेर पर खड़ी होकर बाहर की दुनिया को निहार रही होती है, तब वहां उसने चींटियों की कतारों को देखा है। लेकिन वह मकड़ी के चित्र को नहीं पहचान सकी। अंदर के पन्ने पर चिड़िया, हाथी, पढ़ते हुए बच्चे के बारे में वह एक-दो शब्दों में बता सकी।

पत्रिका के अगले पन्ने पर एक पेड़, पत्ती और महिला का चित्र था। दिलचस्प यह था कि पेड़, पत्ती, जो उसने अपने आसपास देखे हैं, वैसा पत्रिका का चित्र नहीं था मगर उसके दिमाग में पेड़ और पत्ती के चित्र अंकित हो चुके लगते हैं। महिला के चित्र के बारे में जुगनू ने बताया कि यह 'नानी है'। नानी की छवि उसके दिमाग में एक अधेड़ महिला की बनी है। अब मुझे जुगनू के साथ मजा आने लगा था। मैं एक ऐसे अचरज लोक में पहुंच चुका था जहां एक बच्ची ठीक से बोलना नहीं जानती, मगर वह छपी हुई उन चीजों को पहचानने की क्षमता से लैस है, जो उसने अपने परिवेश में देखी है। पौने दो साल की कोई भी बच्ची जो कुछ बोलती है, उससे अर्थ निकालना होता है। हमें यह समझना होगा कि बच्चे हमारे जैसी भाषा नहीं बोलते। जो भी बोलते हैं वह अमानक या अधूरी भाषा नहीं है। हमारे कहने या करने का अर्थ बच्ची निकाल पाती है और वह उसके जवाब में कहती या करती है। लिहाजा बच्ची यह क्षमता जन्म के साथ लेकर ही पैदा होती है।

अगर हम पांच-छह साल के बच्चों की बात करें तो उनके अनुभव अपेक्षाकृत समृद्ध होते हैं। अगर एक पौने दो बरस की बच्ची छपे हुए चित्रों को पहचान लेती है तो स्कूल आने वाले बच्चे कहीं अधिक सक्षम होते हैं। बच्चों को पढ़ना सिखाना हमारे यहां एक ज्वलंत समस्या है। पढ़ना सिखाने के लिए हमारे यहां वर्णमाला, बारहखड़ी, मात्रा ज्ञान, बिना मात्रा वाले सरल शब्द और इसी कड़ी में सरल वाक्य का अनवरत, अर्थहीन सिलसिला जारी रहता है।

शुरुआती तौर पर तैयारी के लिए पढ़ने की अर्थहीन और उबाऊ प्रक्रिया में बच्चों को झोंक देना उन्हें पढ़ने से विलग कर देती है। पढ़ना सिखाने को लेकर बच्चों के साथ जोर-जबर्दस्ती करना हमारी आदत में शुमार हो चुका है। सच पूछें तो इसका एहसास ही नहीं होता कि हम बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। आखिर बच्चे पढ़ना क्यों सीखें? पढ़ने का अर्थ समझने से है। पढ़ने के दौरान लिपि के संकेतों के अर्थ को हमारा दिमाग प्रक्रिया में लाता है और फिर उसे समझता है। जैसे अगर किसी बच्चे ने हाथी, कुत्ते, कुर्सी, पत्ती, पेड़, फूल, फल, बकरी, चम्मच, थाली, बाल्टी, मकड़ी, चींटी आदि को देखा और अंतर्क्रिया की है तो वह उसके दिमाग में इन चीजों की छवि बन जाती है। अगली बार अगर आप कोई और फूल भी दिखाएंगे तो वह उसे पहचान सकता है। पुस्तक में बच्चों के नजरिए से बने चित्रों को पढ़ना भी तो पढ़ना है। यह बच्चों के लिए आसान है। अगला चरण होता है जहां वे किसी घटना को केवल लिपि के रूप में पढ़ते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं।

बच्चों की असीमित क्षमताओं को हमें समझना होगा। आमतौर पर स्कूलों में जो कुछ शिक्षण होता है, वह बच्चों के अनुभवों और संदर्भों को हाशिये पर रख कर चलता है। यह देखा गया है कि बच्चे हो या वयस्क, उनके अपने अनुभवों और संदर्भ की बुनियाद पर सीखना-समझना आसान होता है। बच्चों का दिमाग हर उस अर्थपूर्ण घटना और चीज को पकड़ने को उतावला होता है। स्कूलों को बच्चों की इस तासीर को समझना होगा।

चुनाव में हिंसा

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान के दौरान देश के कुछ राज्यों से हिंसा की खबरें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। सवाल है कि मतदान के समय इतनी सुरक्षा के बीच कैसे राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता या अन्य लोग हिंसा को अंजाम दे देते हैं? कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ राजनेता या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी कमियों को छुपाने के लिए शायद किसी भी हद तक गिर जाते हुए मतदान के दौरान खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं।

यहां यह कहना उचित होगा कि राजनीतिक पार्टियों के गलत आचरण की वजह से मतदाताओं का इन पर से विश्वास उठ चुका है और मतदान में भी रुचि इस कारण हो कम हो गई है। उस पर भी मतदान के समय राजनीतिक पार्टियों की गुंडागर्दी या इनकी आपसी झड़प कारण मतदाताओं के बीच खौफ पैदा कर देती है।

सवाल है कि लोकतंत्र में आखिर हिंसा का क्या काम? अगर मतदान के दौरान ऐसे ही हिंसा का दौर चलता रहा तो फिर कौन निकलेगा वोट डालने? इससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी। चुनाव आयोग को चाहिए कि वह मतदान के दौरान हिंसा या दहशत फैलाने वाली राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखाने के लिए कठोर कदम उठाए। जिस बूथ पर हिंसा की जाती है वहां चुनाव रद्द करके हिंसा फैलाने वाली राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंधित कर दे। अगर चुनाव आयोग इस तरह के कठोर फैसले लेना आरंभ कर देगा तो हरेक राजनीतिक पार्टी का हाईकमान मतदान के दौरान हिंसा या दहशत फैलाने वालों के लिए अवश्य ही कुछ न कुछ गंभीर कदम उठाएगा।

• *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

उत्पीड़न की शिकायत

सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने एक महत्त्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा था कि ससुराल में उत्पीड़न की शिकार महिला मायके से या जहां वह शरण लिए हुए है, वहां से भी मुकदमा दायर करा सकती है। सर्वोच्च अदालत ने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि महिला को उस इलाके में शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है जहां उसकी ससुराल है। पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत अपने आश्रय स्थल या मायके में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकती है। दरअसल, अभी तक महिला को उसी जगह मुकदमा दायर कराना पड़ता था, जहां उसकी सुसराल है। अदालत ने धारा 498 ए की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रताड़नाएं शामिल मानी जाएंगी। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला दहेज पीड़िताओं सहित उन तमाम महिलाओं को राहत देने वाला है जो सिर्फ इसी मजबूरी के चलते अपने उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा पाती हैं कि शिकायत ससुराल के पास पड़ने वाले थाने में ही दर्ज होगी। इससे ऐसी महिलाओं को जल्द न्याय मिलने का रास्ता साफ हो सकेगा।

• *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली (महाराष्ट्र)*

किताबों का महत्त्व

वर्तमान में लोगों में पुस्तकें पढ़ने की रुचि कम हो गई है। टीवी, मोबाइल और इंटरनेट को अधिक समय देना इसका प्रमुख कारण है। आज दुनिया की बेहतरीन पुस्तकें केवल पुस्तकालयों की आलमारियों में ही सुशोभित हो रही हैं। हरेक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में से कुछ समय किताबों को भी देना चाहिए, ताकि इनका फायदा मिल सके। पुस्तकें समाज का दर्पण होती हैं। हमारी सामाजिक मान्यताओं और संस्कृति के साथ-साथ समाज की जानकारी भी पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। बाल गंगाधर तिलक ने पुस्तकों के महत्त्व के बारे में कहा था कि 'मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि उनमें वह शक्ति है कि जहां वे होंगी, वहीं स्वर्ग बन जाएगा।'

• *राजेंद्र कुमावत, जयपुर*

साख पर आंच

बीते तीन-चार सालों से जिस तरह से न्यायपालिका पर आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वह देश के लोकतंत्र और आम आदमी के हित में ठीक नहीं है। न्यायिक प्रणाली में कुछ रसूखदारों के दखल के प्रति अपने रोष को व्यक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय के चार जजों को प्रेसवार्ता करनी पड़ी थी और कहना पड़ा कि न्यायालय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देश के इतिहास में इस प्रकार की यह पहली घटना थी। अब फिर से मुख्य न्यायाधीश के ऊपर अमर्यादित आचरण का आरोप लगा है, जबकि वे कई महत्त्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने वाले हैं। सवाल उठता है कि ऐसे इल्जाम लगा कर क्या वे ताकतें अपने मनमाफिक फैसले करवाने की कोशिश कर रही हैं? क्या यह एक तरह की ब्लैकमेलिंग की जा रही रही है? उच्चतम न्यायालय ने इन सभी मुद्दों का संज्ञान लिया है और जांच कमेटी बनाई गई है। उम्मीद है कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

• *मोहम्मद आसिफ, जामिया नगर दिल्ली*

सरपंचों को प्रशिक्षण

भारत के विकास में ग्राम पंचायत का महत्त्वपूर्ण योगदान है, लेकिन धरातल पर इन उद्देश्यों की पूर्ति देखने को नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर मामलों में ग्राम पंचायत के सरपंच को ही ग्राम पंचायत के अधिकारों की जानकारी नहीं होती और कई सरपंच अशिक्षित होने के कारण खुद के हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते। इस वजह से गांव विकास से वंचित रह जाता है। यों महिलाओं राजनीति में उतरने का पूरा मौका दिया जाता हैं, लेकिन सरपंच का पद मिलने के बाद राजनीतिक समझ के अभाव के कारण वे अधिकारियो पर निर्भर हो जाती हैं और वे खुद के फैसले लेने में असक्षम होती हैं। इसलिए सरपंचों और सदस्यों को विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाने का प्रबंध किया जाना जरूरी है।

• *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली (नागपुर)*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com